

संपादक की कलम से

आर्थिक तंगी के चलते भूखों मरता
पाकिस्तान अब अपनी बदनीयती
की वजह से प्यासे भी मरेगा

आर्थिक तंगी के चलते भूखों मरता पाकिस्तान अब अपनी बदनीयता की वजह से प्यासे भी मरेगा। आर्टिकलों का पनाहगार बने पाकिस्तान का हुक्माना पानी बंद होने वाला है। भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जलसंकट समझौते पर अगे नहीं बढ़ाना चाहता। इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। इस मामले में भारत ने विद्युत में एक तटरथ विशेषज्ञ द्वारा बुलाई बैठक में अपना वक्तव्य दे दिया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के किशनगंगा और रत्ले पनविजली परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा हो गया है। पाकिस्तान इस विवाद का समाधान चाहता है। मगर आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को भारत अब पानी नहीं देना चाहता। यह बैठक इसके समाधान के उद्देश्य से कार्यवाही का हिस्सा थी।

गरतलब ह कि भारत न सिंधु जल समझौता 1960 म संसाधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। 62 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल समझौते में संशोधन की मांग की थी। उसके समय पाकिस्तान को जारी नोटिस इसलिए भी मायने रखता था क्योंकि भारत के कई एक्सपर्ट्स समय-समय पर इस समझौते को रद्द करने की मांग करते रहे हैं। भारत भी इससे पहले पाकिस्तान को पानी रोकने की चेतावनी दे चुका था। पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में भारत के तत्कालीन परिवहन और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि भारत पाकिस्तान में बह रहे अपने हिस्से के पानी को रोक सकता है। सिंधु जल समझौता रद्द होने या भारत की ओर से पानी डायर्वर्ट करने से पाकिस्तान में नदी के पानी पर निर्भर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए संकट पैदा हो सकता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने यह नोटिस 25 जनवरी 2022 को जारी किया था। भारत की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि भारत, पाकिस्तान के साथ जल संधि को पूरी तरह से लागू करने का समर्थक रहा है। लेकिन पाकिस्तान की कर्वावाइयों ने भारत को जरूरी नोटिस जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। नोटिस जारी करने का मुख्य मकसद पाकिस्तान को समझौते के उल्लंघन को सुधारने के लिए 90 दिनों की मोहल्लत देना था। पाकिस्तान नोटिस रिसीव करने के तीन महीने के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता था।

दरअसल सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। लगभग 63 साल पहले हुई सिंधु जल संधि (बहल) के तहत भारत को सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से 19.5 प्रतिशत पानी मिलता रहा है।

भारत की बड़ी जनसंख्या

भारत का बड़ा जनसंख्या वाईवक बाजार का आवश्यकता

भारत की वर्तमान में जनसंख्या भारी-भरकम देश चीन की जनसंख्या से भी ज्यादा हो गई है। यानी कुल मिलाकर एक अरब चालीस करोड़ आबादी वाला भारत में जनसंख्या के बोझ तले विकास और उन्नति बेहद धीमी और अविकसित है। विकसित तथा समृद्ध देश भारत की जनसंख्या में एक संभावना वाला उपभोक्ता बाजार तलाशते हैं और इसे बहुत बड़ी पूँजी भी मानकर अपनी उपभोक्ता सामग्री भारत में बेचने का प्रयास करते हैं। केवल बाजार में निवेश और बाजारी ताकत ही विकास का पैमाना नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी जनसंख्या सीमित संसाधनों को नष्ट कर देती है और विकास की धार को कमजोर करने का काम करती है। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करते हैं तो देश में बिजली, पानी की कमी बढ़ती महंगाई, फैलती विनाशकारी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, अशिक्षा के फैलाव पर नियंत्रण, गरीब व्यक्ति को और गरीब होने से रोकने का प्रभावी तरीका तथा सांप्रदायिक दंगों पर रोक लगाई जा सकती है। कम और नियंत्रित जनसंख्या तेजी से विकास का पैमाना हो सकती है। 1951 से लेकर 81 तक भारत में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इसे जनसंख्या विस्फोट का भी नाम दिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में

महिला आरक्षणः बातें हैं बातों का क्या ?



- 17वा लोकसभा में दशभर से 78 माहला सांसद जीत कर संसद में पहुंची थीं
 - संसद में महिलाओं की यह उपस्थिति 14.36 प्रतिशत है
 - 2014 के लोकसभा चुनाव में 62 महिलाओं ने जीत दर्ज कराई थी
 - 1951 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज पांच प्रतिशत था

परसामन का शत नहीं था। आज भाजपा न भी उस समय परिसीमन जैसी किसी शर्त के बिना ही उस विधेयक का समर्थन किया था। सबाल यह है कि आज जब भाजपा सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के लिए अधिनियम बना रही है तो उसे सबसे पहले परिसीमन से जोड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? क्या इसी लिये नए ह्यारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया है। जिसमें कहा गया है महिला आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य होगा? माना जा रहा है कि परिसीमन का मकसद लोकसभा सीटें बढ़ाना भी हो सकता है। गैरतलब है कि 2021 में होने वाली जनगणना भी अभी तक नहीं हुई है। यदि सब कुछ निर्बाध रूप से और बिना किसी टाल मटोल के हुआ तो शायद महिला आरक्षण 2026 से लागू हो सके अन्यथा अनिश्चितता की सूरत बनी रहेगी। हालांकि सरकार ने यह जरूर बता दिया है कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लागू होने से लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। यह

मा बताया गया है कि 15 वष के लिए
आरक्षण का प्रावधान है हालांकि संसद को
इसे बढ़ाने का अधिकार होगा।

बहरहाल

महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के
बाद अनेक विशेषकों व राजनीतिज्ञों की
तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
कांग्रेस चाहती है कि इसे तत्काल लागू
किया जाये। इसे लागू करने के लिए
जनगणना या परिसीमन की कोई जरूरत
नहीं है। जबकि कुछ का मत यह भी है कि
जब महिलाओं का आधी आबादी कहकर
सम्बोधित किया जाता है तो उनके लिये
आरक्षण भी 33 प्रतिशत क्यों, 50 प्रतिशत
क्यों नहीं? और यदि वास्तव में सरकार की
नीतियत महिला आरक्षण अधिनियम को
लेकर साफ है तो परिसीमन व जनगणना
जैसे बहानों की जरूरत क्या? जिस तरह
भाजपा द्वारा दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में
महिलाओं को इकट्ठा कर बाकायदा जश्न
मनाकर प्रधानमंत्री का महिला आरक्षण
अधिनियम के लिये पार्टी की महिलाओं
द्वारा धन्यवाद किया गया और उन्हें
महिलाओं का इस सदी का सबसे बड़ा

नायक व जीतहास पुरुष बताने का काशशश की गयी उससे कम से कम एक बात तो स्पष्ट है कि बावजूद इसके कि आगामी विधानसभा व लोकसभा किन्हीं भी चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा परन्तु इसके बावजूद यह भी तय है कि महिला आरक्षण का यह मुद्दा निकट भविष्य के सभी चुनावों में मुख्य मुद्दा बनने वाला है। इसे इसलिये जरूर सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि सरकार ने आधी आबादी के प्रति अपनी हमदर्दी का सन्देश भी दे दियाहा और पुरुषों का वर्चस्व भी फिलहाल यथावत बना रहने दिया। तो क्या केवल चुनावी लाभ हासिल करने की गरज से ही यह सारी कावयद की गयी ? जिससे तरह संसद के नये भवन में महिला आरक्षण के रूप में पहला विधेयक पेश किया गया और उसे ऐतिहासिक समर्थन के साथ पूर्ण बहुमत से पारित भी करा लिया गया इससे बेशक यह सकेत तो मिलता है कि सरकार आधी आबादी की हित चिंतक है। परन्तु इन सवालों से भी यही सरकार कैसे बच सकती है कि जब इसी वर्ष 28 मई को नये संसद

भवन का उद्घाटन किया गया था उस समय देश की महिला राष्ट्रपति को इस भवन के उद्घाटन हेतु क्यों आवांत्रित नहीं किया गया था ? जबकि वह उनका अधिकारी भी था और यदि वे उद्घाटन करतीं तो राष्ट्रपति के महिला होने के नाते आज अच्छा सन्देश भी जाता ? और जब बात नये संसद भवन के उद्घाटन की होती है तो उस दिन को देश इसलिये भी नहीं भूल सकता क्योंकि उसी दिन विश्व में देश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं ने जो एक भाजपा सांसद द्वारा उनका यौन शोषण किये जाने के चलते जंतर मंतर पर धरना दे रही थीं उन्होंने उसी 28 मई को नये संसद भवन के सामने महिला पंचायत आहूत की थी जिसे सरकार ने बल्पूर्वक होने नहीं दिया। यहाँ तक कि महिला खिलाड़ियों का तम्बू भी धरना स्थल से उखाड़ फेंका। महिला आरक्षण पर हुई चर्चा के दौरान पंजाब की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने भाषण में जहां देश में महिलाओं की वास्तविक स्थिति बयान करने की कोशिश की वहां वे यह बताने से भी नहीं चूकीं कि महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोपी भाजपा सांसद इस समय भी लोक सभा में मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने भी याद दिलाया कि देश के लिये स्वर्ण पदक लेने वाली महिलायें धरने पर थीं जबकि उनका शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी आज संसद में बैठा है ? इसी विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सांसदों ने मणिपुर में महिलाओं को नगन धुमाये जाने, महिलाओं के प्रति हो रहे राष्ट्रव्यापी अपराध, देश में बढ़ती जा रही बलात्कार की घटनाओं का भी जिक्र किया। बहरहाल सत्ता और विपक्ष खासकर भाजपा व कांग्रेस के बीच महिला आरक्षण का श्रेय लेने की बातें तब तक बेमानी और महिलाओं को भ्रमित करने वाली हैं जब तक यह लागू नहीं हो जाता। इस अधिनियम को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' जैसा लोकलुभावन नाम दिया जाना भी तब तक मीठी बातें ही हैं। और तब तक महिला आरक्षण की बातें सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या ?

ओबोसी के नाम पर बेवकूफ बनाने का ड्रामा

-डा सत्यवान सारभ आंकड़ों का अध्यन करे पाएंगे कि देश के कुल विश्वविद्यालयों में अन्य वर्ग में केवल ५ उप-कुल अगर रजिस्ट्रर देखें तो समाज के तीन हैं। देश वे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरियल सीटों की मात्र ४.५ प्रतिशत गई हैं। अमूमन यही एसोसिएट और असिस्टेंट में भी है। सीटों के खाली साथ-साथ ओबीसी वे क्रीमीलेयर का घटिय खेलकर उनको कहीं का छोड़ा जा रहा है जिसकी उनकी जाति का सर्टिफिकेट छिना जा रहा है। छह लाख की मामूली सीमा से का हक मारकर आने वाले को पंगु बनाया जा रहा है अन्य अरक्षित वर्गों में न क्रीमीलेयर है न को बाध्यता? जिसकी वजह से वर्गों के बड़-बड़े अफ

बच्च भा पांडिया तक आरक्षण का फायदा उठा पाएगे। बड़े समाज को पीछे छोड़ हम अपने देश को सशक्त नहीं कर सकते। क्या यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सारे तथ्यों को जानते हुए भी सरकारों द्वारा ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया जा रहा है?

सांप्रदायिकता और आरक्षण ने भारी संख्या में युवाओं का मानसिक और राजनीतिक विकास रोक दिया है। उन्हें कुठित बना दिया है। उनकी जरूरत समाप्त हो चुकी है क्योंकि वे सामाजिक न्याय की मुख्यधारा से कट गए हैं। काट दिया गया है। इन दो नफरतों के कारण जरूरत ही समाप्त हो चुकी है। बेहतर है आप आरक्षण के महत्व को समझें। उसके नाम पर खुद को मुख्यधारा से अलग न करें। अपने भीतर जातिगत नफरत को मिटाइये। थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस नफरत से मुक्ति मिल जाएगी। आप अच्छा महसूस करेंगे। सभी समाज के लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि आरक्षण के कारण अवसर खत्म नहीं होते हैं। अवसर खत्म होते हैं दूसरी नीतियों के कारण। चार पूँजीपातियों की पूँजी बढ़ती रहे इसके लिए आर्थिक नीतियों का जाल बिछाने के कारण अवसर समाप्त होते हैं। लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि उनकी नौकरी में रुकावट आरक्षण नहीं है। अवसर की कमी है। सरकार की मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण अवसर समाप्त हो चुके हैं। प्राइवेट हों या सरकारी क्षेत्र में। ये आरक्षण के कारण नहीं हुआ है। चौंकि आप आर्थिक जगत के मुश्किल खेल को नहीं समझ पाते तो फिर से आरक्षण पर पहुँच जाते हैं कि इसकी वजह से नौकरी नहीं मिल रही है। जबकि जिन्हें आरक्षण मिला है उन्हें भी नौकरी नहीं मिल रही है।

अब आते हैं ओबीसी पर। केवल केंद्र सरकार के संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को जोड़ लें तो पता चलेगा कि ओबीसी के चालीस से साठ फीसदी तक पद खाली हैं।

गंभीर इकोनॉमिक क्राइस्ट झेल दहा है पाकिस्तान !

सुनील कुमार पाकिस्तान इन दिनों गंभीर अर्थक संकट(इकोनोमिक क्राइसेस) झेल रहा है और पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में भुखमरी बढ़ी है। सच तो यह है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ही बुरे हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि पाकिस्तान में आम लोगों को दो वक्त की रोटी तक भी नसीब नहीं हो पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में पाकिस्तान में रोटी, दाल, चावल और आटा के लिए लोग लगातार भटक रहे हैं। दाल, चावल और आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल है। यहां पेट्रोल के दाम 26.02 पाकिस्तानी रुपए बढ़कर 331.38 रुपए हो गए। वहीं हाई-स्पीड डीजल 17.34 रुपए बढ़कर 329.18 पाकिस्तानी रुपया हो गया। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक, पिछले एक महीने में पेट्रोल-डीजल के रेट में करीब 58.43 और 55.83 रुपए की बढ़ोत्तरी दरअसल, अगस्त में इंफ्लेशन 27.4% से ज्यादा की वृद्धि बाद पेट्रोलियम की कीमतें बालै दिनों में सामान्य कीमतें आसार हैं। जानकारी देना पाकिस्तान में भोजन के लिए झड़प, लड़ाई झगड़ा करते स्वीकार वास्तव में पारिवारिक बदहाली को ही बयां व पाकिस्तान के हालात अखिल ? सच तो यह है कि पाकिस्तान और बेरोजगारी अपने चरम यहां यह बात भी कह सकता है कि पाकिस्तान आजकल कंगाल है और आम जनता का हाल बेहाल हो रहा है। पिछले साल से तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था ही डांवाडोल और यह बात आंकड़ों से चलती है। विश्व बैंक ने

पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि वर्ष 2022-23 में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4 प्रतिशत का स्तर छू चुकी है। वास्तव में गरीबी के यह आंकड़े अत्यन्त ही चौंकायने वाले हैं। आंकड़ों के अनुसार खराए और आर्थिक हालात के कारण पाकिस्तान में 1.25 करोड़ से अधिक नए लोग इसके चर्चेट में आए हैं जिनके बैंक ने पाकिस्तान के बारे में यह कहा है कि वित्तीय स्थिरता दोहरातार हासिल करने के लिए पाकिस्तान का तत्काल कदम उठाने होंगे, अन्यथा अब तक इसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी एक साल के भीतर 34.2 प्रतिशत से बढ़कर 39.4 प्रतिशत हो गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में 1.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। जानकारी देना चाहूंगा विश्व पाकिस्तान में 3.65 अर्थात् डॉलर प्रतिदिन के आय स्तर को गरीबी रेखा पार करना जाता है। मसौदा नीति में कहा गया था कि

कि लगभग 9.5 करोड़ पाकिस्तानी अब गरीबी में रहते हैं, जबकि उसकी कुल जनसंख्या 23 करोड़ के करीब है। इससे हम यह सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में गरीबी किस कदर हावी है ? यह बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है कि पाकिस्तान में इस वर्ष हालात पिछले वर्ष के मुकाबले और भी अधिक खराब हो गये हैं। पिछले वर्ष गरीबी का आंकड़ा 34.2 प्रतिशत था अब वह आंकड़ा 39.4 प्रतिशत का स्तर छू चुका है। सच तो यह है कि इन दिनों पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और मानव विकास को लेकर अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में बिजली की दरें बहुत अधिक हैं और लोग बिजली की दरें चुकाने में समर्थ नहीं हैं। पहले से बिजली की बढ़ी दरों को झेल रहे पाकिस्तान की आम जनता को हाल ही में एक ओर झटका लगा है।

असल, पाकिस्तान के नेशनल प्रैटिक्ट्रक पावर रेगुलेटरी अथारिटी ने जली बिल में 3.28 पाकिस्तानी रूपए देते यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया। यहाँ पाठकों को यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ समय पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बिजली प्रभोक्ताओं को सब्सिडी देने से पाकिस्तान सरकार को रोक दिया था। हाँ पाठकों को यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में उस समय बढ़े लोंगों को लेकर पाकिस्तान में व्यापक गर्दान पर बहुत से विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे।

उत्तरहाल, उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक प्रमुख अर्थशास्त्री टोबियास हक ने हाँ कि पाकिस्तान का आर्थिक मॉडल बदल गरीबी कम नहीं कर रहा है और मकाक्ष देशों के मुकाबले यहाँ जीवन और घट रहा है। विश्व बैंक ने कृषि और यल एस्टेट पर कर लगाने तथा बेकार

बच में कटीता करने का आग्रह किया यह बहुत ही गंभीर है कि पाकिस्तान दोगों की रोजाना कमाई भारत के 300 ए से भी कम है। पाकिस्तान के लात ऐसे हो गये हैं कि उसको अपनी लाइन तक बेचनी पड़ रही है। आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार (रेक्स रिजर्व) गिरता जा रहा है और ड रिजर्व भी उसी तेजी से घट रहा पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले बुरी से दबा हुआ है। बहरहाल, वास्तव वर्क संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार को जितनी जलदी अपेक्षे के विदेशी कर्ज हासिल करना होगा। इन, यहां यक्ष सवाल ये पैदा होता है आखिर पाकिस्तान को कर्ज देगा ? पहले ही पाकिस्तान पर बहुत सा शी कर्ज है। जानकारी देना चाहूँगा आई एम एफ(अंतरराष्ट्रीय मुद्रा) तबतक पाकिस्तान को पैसे देने से

कर चुका है, जबतक वो उसकी शर्तों को मानने के साथ उनपर नहीं करता। वहीं सऊदी अरब तान को बिना ब्याज के कर्ज देने कार कर चुका है। यहां तक कि पाकिस्तान को किसी भी तरह का नने से बचता नजर आ रहा है। हाल तल, वर्ल्ड बैंक ने उपर्युक्त ट्रू-जीडीपी अनुपात में तुरंत 5% थ और एक्सप्रेडिंगर्स यानी व्यय में वो के लगभग 2.7% की कटौती जानी चाहिए। इससे अस्थिर वस्था को वापस पटरी पर लाया करता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड बैंक करी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी बताया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ट्रू- जीडीपी अनुपात में 5% का करने के लिए टैक्स छूट को वापस जा सकता है। इसके अलावा रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर्स पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है।

